



# EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS

EPCH HOUSE, POCKET 6 & 7, SECTOR 'C', LOCAL SHOPPING CENTRE, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070

Tel: 91-11-26135256

Fax: 91-11-26135518,26135519

Email: [press@epch.com](mailto:press@epch.com)

web: [www.epch.in](http://www.epch.in)

## PRESS RELEASE

### EPCH RAISES ISSUE OF UNAVAILABILITY OF CONTAINERS FOR EXPORTS OF HANDICRAFTS WITH RAILWAYS, COMMERCE AND SHIPPING MINISTERS

NEW DELHI – 7<sup>th</sup> October 2020 – In order to ensure that handicrafts sector keeps growing at a brisk pace and continue to earn much needed foreign exchange and provide livelihood to millions, it is important that the logistic system (availability and movement of containers) should support and compliment the efforts made by the artisans and exporters.

Mr Ravi K Passi, Chairman-EPCH drew attention of the Railways Commerce and Shipping Ministers towards the problem of the shortage of availability of containers for exports and said that the current Covid crisis has resulted in the decline of exports of handicrafts by (-) 34.75% during the April –September of the current financial year 2020-21 and after the Government's relaxation given under unlock-1 to 5, business activity has resumed and exports are beginning to take place, however, any disruption at this critical stage in shipments would deal a severe blow to all the export promotion efforts of all the stakeholders.

Adding further, he said, handicrafts is one of the worst affected sector on account being the voluminous cargo shipments. He also raised the issue of repo charge (repositioning charge) ranging from Rs.10,000/- - Rs. 20,000/- which the exporter has to bear in case he wishes to source the container from the nearby ICDs thus incurring additional transaction cost and also the increase of 20 to 40% in shipping charges.

Shri Rakesh Kumar, Director General – EPCH urged the Government to consider establishment of a Regulatory Authority through enactment of the Parliament to control and monitor the pricing, terms & conditions and other provisions relating to the shipment of goods. The current shipping lines are arbitrarily deciding the pricing and imposing conditions at their whims and fancies.

Mr. Passi has requested all the concerned ministries to urgently look into the matter, so that exports from the country can continue without any hindrance as the interventions of the concerned Minister's would certainly help facilitate timely shipments of the export consignments and thereby promote exports from the country.

---

#### For more information, please contact :

Shri Rakesh Kumar, Director General - EPCH - +91-9818272171

Follow us on #epchindia





# EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS

EPCH HOUSE, POCKET 6 & 7, SECTOR 'C', LOCAL SHOPPING CENTRE, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070

Tel: 91-11-26135256

Fax: 91-11-26135518,26135519

Email: [press@epch.com](mailto:press@epch.com)

web: [www.epch.in](http://www.epch.in)

## प्रेस विज्ञप्ति

### ईपीसीएच (EPCH) ने रेलवे वाणिज्य और नौवाहन मंत्रालयों और मंत्रियों को निर्यात के लिए हुई कंटेनरों की कमी का मुद्दा उठाया

**नई दिल्ली - 7 अक्टूबर 2020** - हस्तशिल्प निर्यात के गति को बनाए रखने; देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने और लाखों लोगो तो जीविका प्रदान करने हेतु, यह अत्यंत आवश्यक है कि कंटेनर की उपलब्धता और आवाजाही को सुनिश्चित किया जाये ।

श्री रवि के पासी, अध्यक्ष-ईपीसीएच ने निर्यात के लिए कंटेनरों की उपलब्धता की कमी की समस्या की ओर रेलवे वाणिज्य और जहाजरानी मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि वर्तमान कोविड संकट के परिणामस्वरूप हस्तशिल्प निर्यात घट गया है (- 34.75) अप्रैल-चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान (-34.75%) की गिरावट आई है और अनलॉक -1 से 5 के तहत सरकार की छूट के बाद, व्यावसायिक गतिविधि फिर से शुरू हो गई है और निर्यात होने लगे हैं, अतः इस महत्वपूर्ण चरण में शिपमेंट में कोई भी व्यवधान सभी हितधारकों और निर्यातकों के लिए एक गंभीर झटका साबित हो सकती हैं ।

उन्होंने आगे कहा, हस्तशिल्प मालवाहक शिपमेंट से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र में से एक है। उन्होंने रिपो चार्जस का मुद्दा भी उठाया जिसके तहत निर्यातक को रुपया 10,000 से लेकर रुपया 20000 तक की धनराशि खर्च कर कंटेनर दूसरे आईसीडी से मंगाना पड़ता है इसके अलावा उन्होंने शिपिंग शुल्क में 20 से 40% की वृद्धि मुद्दा भी समक्ष रखा ।

श्री राकेश कुमार, महानिदेशक - ईपीसीएच ने सरकार से माल के शिपमेंट से संबंधित मूल्य निर्धारण, नियमों और शर्तों और अन्य प्रावधानों को नियंत्रित और निगरानी करने के लिए संसद के अधिनियमन के माध्यम से नियामक प्राधिकरण की स्थापना पर विचार करने का आग्रह किया। वर्तमान की शिपिंग लाइनें मनमाने ढंग से मूल्य निर्धारण और शर्तें थोप रही हैं।

श्री पासी ने सभी संबंधित मंत्रालयों से इस मामले को तत्काल देखने का अनुरोध किया है, ताकि देश से निर्यात बिना किसी बाधा के जारी रह सके क्योंकि संबंधित मंत्री के हस्तक्षेप से निश्चित रूप से निर्यात खेपों के लदान में सुविधा होगी और जिससे देश के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

**अधिक जानकारी के लिए, संपर्क करें:** श्री राकेश कुमार डायरेक्टर जनरल, EPCH- +91-9818272171

Follow us on #epchindia



Follow us on #epchindia

